

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2684/2015

महेश चन्द शर्मा

—अपीलार्थी

## बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), भरतपुर।

## —प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.10.2015  
आदेश की दिनांक : 05.02.2024

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.सी. गुप्ता, अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.02.1988 (अनुलग्नक-1) द्वारा नियोजन कार्यालय जोधपुर से प्राप्त सूची के आधार पर एवं साक्षात्कार के आधार पर अध्यापक के पद पर अस्थाई रूप से सत्र समाप्ति तक नियुक्त किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बालेसर द्वारा आदेश दिनांक 02.08.1988 (अनुलग्नक-2) द्वारा आदेश दिनांक 27.02.1988 की निरंतरता में 6 माह के लिए पुनः नियुक्त किया गया और 6 माह बाद उसे निरंतर सेवा में रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.01.1995 (अनुलग्नक-3) द्वारा जिला स्थापना समिति, जिला परिषद जोधपुर द्वारा अस्थाई रूप से कार्यरत अध्यापकों की समीक्षा की जाकर उनकी सेवाएं नियमित की गई, जिसमें अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 03.08.1988 से नियमित किए जाने का अंकन है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.01.1992 की अनुपालना में अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 03.08.1997 से स्वीकृति जारी की गई है (अनुलग्नक-4)। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.03.2013 (अनुलग्नक-5) द्वारा द्वितीय चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि 02.01.1995 मानते हुए दिनांक 02.01.2013 से स्वीकृति जारी की गई। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 27.07.2015 (अनुलग्नक-6) द्वारा न्याय की मांग हेतु नोटिस भी प्रस्तुत किया गया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.03.2013 (अनुलग्नक-5) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 03.09.2006 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी तौर पर जिला परिषद सेवा चयन आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने या कार्यग्रहण करने की तिथि से 6 माह के लिए अथवा राज्य सरकार के अन्य निर्देश तक जो भी पहले हो की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति/स्कीनिंग होने की तिथि से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबंधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी विधि अनुसार देय परिलाभ स्वीकार करता आ रहा है और बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे विलम्ब बाद बिना और विलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। विभागीय विधि अनुरूप नियमितकरण आदेश/स्कीनिंग की तिथि से लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय की पालना में जारी आदेश दिनांक 20.03.2013 विधिक होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दायर खण्डपीठ याचिका 650/2016 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 के अनुसार ही अपीलार्थी सेवा संबंधी समस्त लाभ परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.03.2013 (अनुलग्नक-5), जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 02.01.1995 से मानते हुए द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 02.01.2013 को स्वीकृत किया गया है, को चुनौती दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.02.1988 (अनुलग्नक-1) द्वारा नियोजन कार्यालय जोधपुर से प्राप्त सूची के आधार पर एवं साक्षात्कार के आधार पर अध्यापक के पद पर अस्थायी रूप से सत्रावसान तक नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.01.1995 (अनुलग्नक-3) द्वारा जिला स्थापना समिति, जिला परिषद जोधपुर द्वारा अस्थायी

रूप से कार्यरत अध्यापकों की समीक्षा की जाकर उनकी सेवाएं नियमित की गई, जिसमें अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 03.08.1988 से नियमित किए जाने का अंकन है। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 03.08.1997 से स्वीकृति जारी की गई है (अनुलग्नक-4) परन्तु आलौच्य आदेश द्वारा द्वितीय चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि 02.01.1995 मानते हुए दिनांक 02.01.2013 से स्वीकृति जारी की गई है। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग हेतु नोटिस भी प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक-6) परन्तु उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी सेवाओं की नियमितिकरण की तिथि 02.01.1995 से द्वितीय चयनित वेतनमान को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3620 / 2009, 2848 / 2006 राजस्थान राज्य अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलार्थी नियमित नियुक्ति स्क्रीनिंग होने की तिथि से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबंधित समस्त परिलाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। अपीलार्थी को राज्य सरकार के अधिकसूचना दिनांक 13.07.2009 के अनुसार स्क्रीनिंग के बाद आदेश जारी होने की तिथि से अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति मानते हुए द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा दायर खण्डपीठ याचिका 650 / 2016 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 के अनुसार ही अपीलार्थी सेवा नियमितीकरण आदेश की तिथि से सेवा संबंधी समस्त लाभ परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि जिला स्थापना समिति जिला परिषद जोधपुर द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 03.08.1988 से नियमित की गई है और उसी आधार पर अपीलार्थी को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 03.08.1997 से प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। आलौच्य आदेश दिनांक 20.03.2013 में नियुक्ति तिथि 02.01.1995 अंकित की गई है, जबकि दिनांक 02.01.1995 को जारी आदेश द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 03.08.1988 से नियमित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमित नियुक्ति के पश्चात ही सेवा संबंधी परिलाभ प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा निर्णय कर अभिनिर्धारित किया है कि नियमित नियुक्ति

तिथि से कर्मचारी चयनित वेतनमान प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया है:—

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay

down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 03.08.1988 से नियमित किया गया है। लिहाजा अपीलार्थी नियमितिकरण की तिथि 03.08.1988 से ही चयनित वेतनमान प्राप्त करने हेतु पूर्ण अधिकारी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 20.03.2013 (अनुलग्नक-5) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने हेतु नियमितीकरण दिनांक 03.08.1988 से सेवा अवधि की गणना की जाकर अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावे। साथ ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विलम्ब अवधि के लिए 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य